



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 606]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 5, 2004/आषाढ़ 14, 1926

No. 606]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 5, 2004/ASADHA 14, 1926

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बीमा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2004

का.आ. 778(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का नाम साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2004 है।
- (2) इसमें इसके पश्चात् जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय इस स्कीम के उपबंध 31-3-2004 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
2. साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995 में, पैराग्राफ 13 में उप-पैरा (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—  
“(क) न्यास, यथास्थिति, प्रत्येक कर्मचारी या उसके कुटुम्ब के संबंध में उस समय जब इस स्कीम के अधीन कर्मचारी या उसका कुटुम्ब फायदों के लिए पात्र हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाने पर कुटुम्ब पेंशन के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) में रजिस्ट्रीकृत भारत में जीवन बीमा कम्पनियों में से किसी से तत्काल वार्षिकियां खरीदेगा;”।

[फा. सं. 2(9)/आईएनएस-III/2003]

जी. सी. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव (बैंकिंग एवं बीमा)

टिप्पण :—मूल स्कीम अधिसूचना सं. का. आ. 585(अ), तारीख 28 जून, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई :—

1. का. आ. सं. 475 (अ), तारीख 3 जुलाई, 1996
2. का. आ. सं. 342 (अ), तारीख 22 अप्रैल, 1997
3. का. आ. सं. 461 (अ), तारीख 18 जून, 1999
4. का. आ. सं. 1221 (अ), तारीख 6 दिसम्बर, 1999
5. का. आ. सं. 590 (अ), तारीख 22 जून, 2000
6. का. आ. सं. 775 (अ), तारीख 13 अगस्त, 2001, और
7. का. आ. सं. 1086 (अ), तारीख 2 नवम्बर, 2001

## स्पष्टीकरण ज्ञापन

1. यह सत्यापित किया जाता है कि अधिसूचना द्वारा किसी पब्लिक सेक्टर (साधारण बीमा) कम्पनियों के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
2. स्कीम का संशोधन वित्त मंत्री के अनुमोदन की तारीख से प्रभावी होगा।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(INSURANCE DIVISION)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2004

**S.O. 778(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 17-A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby makes the following scheme, further to amend the General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995, namely :—

1. (1) This scheme may be called the General Insurance (Employees') Pension (Amendment) Scheme, 2004.
- (2) Save as otherwise provided hereinafter, the provisions of this scheme shall be deemed to have come into force with effect from 31-03-2004.
2. In the General Insurance (Employees) Pension Scheme, 1995, in paragraph 13, for sub-paragraph (a), the following shall be substituted, namely :—
- “(a) The Trust shall purchase immediate annuities from the Life Insurance Corporation of India or any of the Life Insurance Companies in India registered with Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) in respect of each employee or his family as the case may be at the time of he or his family becomes eligible for the benefits under this scheme or, in respect of family pension, on his death.”

[F. No. 2(9)/Ins. III/2003]

G. C. CHATURVEDI, Jt. Secy. (Banking &amp; Insurance)

**NOTE :—**The principal Scheme was published vide notification No. S.O. 585(E), dated 28th June, 1995 and subsequently amended as under :—

1. S.O. No. 475 (E) dated 3rd July, 1996
2. S.O. No. 342 (E) dated 22nd April, 1997
3. S.O. No. 461 (E) dated 18th June, 1999
4. S.O. No. 1221 (E) dated 6th December, 1999
5. S.O. No. 590 (E) dated 22nd June, 2000
6. S.O. No. 775 (E) dated 13th August, 2001 and
7. S.O. No. 1086 (E) dated 2nd November, 2001

## EXPLANATORY MEMORANDUM

1. It is certified that no employee of any of the Public Sector (General Insurance) Companies is likely to be affected adversely by the notification.
2. The amendment of the Scheme will be effective from the date of approval by the Finance Ministry.